सं. ए-42011/01/2023-समन्वय
भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
समन्वय प्रभाग
***

निर्माण भवन, नई दिल्ली,
दिनांक: 01 जूलाई, 2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय: मंत्रिमंडल के लिए मई, 2024 माह प्रमुख गतिविधियों पर मासिक सारांश।

अधोहस्ताक्षरी को आवास और शहरी कार्य मंत्रालय की प्रमुख गतिविधियों पर अवर्गीकृत मासिक सारांश की एक प्रति मई, **2024** के माह के लिए अग्रेषित करने का निदेश दिया गया है।

सलग्नक: यथोपरोक्त

(हरि मोहन झा)
अवर सचिव,भारत सरकार
दूरभाष-23061047

सेवा में,
मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य।

संलग्नकों सहित अग्रेषित प्रति:

1. भारत सरकार के सभी सचिव,
2. आईटी सेल, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।

अनुलग्नक

मई, 2024 माह के दौरान आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से संबंधित महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों/कार्यक्रमों का सारांश नीचे दिया गया है:

I. चिंतन शिविर

मंत्रालय ने 29 से 30 मई 2024 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में "शहरी भारत की पुनर्कल्पना" विषय पर दो दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया। शिविर का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों के बारे में मंथन करना और इन चुनौतियों को कम करने के लिए अभिनव तरीकों पर विचार-विमर्श करना था ताकि नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सके। जिन पाँच व्यापक क्षेत्रों पर विचार-विमर्श हुआ वे निम्न थे:

i. शहरी शासन की पुनर्कल्पना
ii. शहरी नियोजन और शहरों को आपदा प्रतिरोधी बनाना
iii. अर्बन मोबिलिटी
iv. अभिनव शहरी वित्तपोषण
v. किफायती आवास, शहरी अर्थव्यवस्था और सामाजिक इंफ्रास्ट्रकचर

उपरोक्त विषयगत क्षेत्रों में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रधान सचिवों, शहरी विकास विभागों के निदेशकों, नगर आयुक्तों, शिक्षाविदों और क्षेत्र के विशेषज्ञों से युक्त कार्य समूह थे। इस कार्यक्रम में 300 से अधिक प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी देखी गई। स्थानीय हस्तक्षेप, स्थानीय परिस्थितियों पर आधारित समाधान, केस स्टडीज और दुनिया भर चुनी गई सर्वोत्तम प्रथाओं पर चर्चा की गई। समग्र रूप से, इसमें स्थायी शहरों के निर्माण और शहरी शासन के विभिन्न पहलुओं में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

II. स्मार्ट सिटी मिशन

i. दिनांक 18.05.2024 को नई दिल्ली में सीआईटीआईआईएस 2.0 कार्यशाला आयोजित की गई। सीआईटीआईआईएस 2.0 कार्यक्रम के तहत चयनित 18 स्मार्ट शहरों के 100 से अधिक अधिकारियों ने कार्यशाला में भाग लिया।
ii. न्यू टाउन कोलकाता आईसीसीसी दिनांक 22.05.2024 को न्यू टाउन कोलकाता के विभिन्न स्थानों से सैटेलाइट डेटा, समाचार और सीसीटीवी फुटेज का उपयोग करके वास्तविक समय में रीमल चक्रवात की निगरानी कर रहा है।
iii. अगरतला स्मार्ट सिटी में दिनांक 27.05.2024 को डिजिटल आगंतुक प्रबंधन और पर्यटन विपणन पर क्षमता विकास कार्यशाला आयोजित की गई।

iv. पणजी स्मार्ट सिटी ने 28.05.2024 को (निर्धारित समय से पहले) सेंट इनेज़ में दो प्रमुख सड़कें खोली। इन सड़कों में विवांता जंक्शन से शीतल जंक्शन और शीतल जंक्शन से कैकुलो मॉल जंक्शन तक का हिस्सा शामिल है।

v. इस महीने के दौरान 220 करोड़ रुपये की लागत वाली 28 परियोजनाएं पूरी की गई। स्मार्ट सिटी योजना के तहत 1,41,500 करोड़ रुपये की लागत वाली कुल 7,066 परियोजनाएं पूरी की गई हैं।

III. अटल नविनिकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत)

अमृत

i. माह के दौरान 140 करोड़ रुपये की लागत की 12 परियोजनाएं पूरी हुई।

ii. माह में कुल 144 करोड़ रुपये के कार्य निष्पादित किये गये।

iii. अब तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 83,357 करोड़ रुपये की 6,000 परियोजनाएं शुरू की हैं, जिनमें से 77,293 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का कार्य जमीनी स्तर पर निष्पादित किया गया है।

अमृत 2.0

मासिक उपलब्धि

i. 49 करोड़ रुपये की लागत वाली 53 परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को मंजूरी दी गई।

ii. 584 करोड़ रुपये की लागत वाली 54 परियोजनाओं के लिए निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) जारी कर दी गई है।

iii. 975 करोड़ रुपये की लागत वाली 52 परियोजनाओं के लिए संविदा की जा चुकी हैं।

संचयी उपलब्धि

- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 1,82,583 रूपये की लागत से 8,200 परियोजनाओं के लिए राज्य जल कार्य योजनाओं को मंजूरी दी गई है।

i. 1,12,800 करोड़ रूपये की लागत वाली 5,900 परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को मंजूरी दी गई।

ii. 97,687 करोड़ रुपये की लागत वाली 4,924 परियोजनाओं के लिए निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) जारी की गई है।

iii. 63,523 करोड़ रुपये की लागत वाली 3,634 परियोजनाओं के लिए संविदा प्रदान की गई है।

iv. 698 करोड़ रूपये की लागत वाली 471 परियोजनाओं का कार्य पूरा हो चुका है।

IV. दीनदयाल अन्त्योदय योजना/ राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई/एनयूएलएम)

- माह के दौरान 7,814 स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) गठित किए गए। 5148 लाभार्थियों को व्यक्तिगत एवं सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए ऋण प्रदान किए गए तथा एसएचजी-बैंक लिंकेज कार्यक्रम के अंतर्गत 124 ऋण एसएचजी को दिए गए। 4,420 एसएचजी को रिवाल्विंग फंड दिया गया।

- मिशन की शुरुआत से लेकर (14.06.2024 तक) कुल 9,46,949 एसएचजी बनाए गए हैं और 6,13,444 व्यक्तिगत लाभार्थियों और 3,32,539 समूह लाभार्थियों को 8,569 करोड़ रुपये के ऋण से सहायता दी गई है। कुल मिलाकर, 6,55,011 एसएचजी को रिवॉल्विंग फंड दिया गया है।

V. पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मा निर्भार निधि (पीएम स्वनिधि)

पीएम स्वनिधि के अंतर्गत 1,07,93,958 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से मई 2024 तक 89,01,857 स्वीकृतियां और 85,17,124 ऋण वितरण किए गए हैं।

VI. प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)/सभी के लिए आवास (एचएफए)

i. प्रारंभ से अब तक, मिशन ने 1.19 करोड़ आवासों को मंजूरी दी है, जिनमें से 114.28 लाख आवासों के निर्माण की आधारशिला रखी जा चुकी है, तथा 83.51 लाख आवास पूरे हो चुके हैं/सुपुर्द किए जा चुके हैं।

ii. माह के दौरान 225.87 करोड़ रुपए जारी किए गए, जिससे जून 2015 से अब तक कुल 1,63,926 करोड़ रुपए जारी किए गए।

VII. आवास

भू संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 2016 के अंतर्गत माह में की गई प्रगति:

7. 2,877 भू संपदा परियोजनाएं पंजीकृत की गईं
8. 533 भू संपदा एजेंट पंजीकृत किये गये
9. विभिन्न भू संपदा विनियामक प्राधिकरणों द्वारा 403 शिकायतों का निपटारा किया गया

देश भर में कुल 1,28,239 भू संपदा प्रोजेक्ट और 87,814 रियल भू संपदा एजेंट रेरा में पंजीकृत हैं। रेरा द्वारा निपटाई गई शिकायतों की कुल संख्या 1,23,060 है।

VIII. केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी)

i. 28 मई, 2024 को हिमाचल प्रदेश के बनखंडी में प्राणी उद्यान के विकास के लिए **हिमाचल प्रदेश चिड़ियाघर संरक्षण एवं प्रजनन सोसायटी** और **सीपीडब्ल्यूडी** के बीच **समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।**

ii. 15 मई, 2024 को मेडक, हैदराबाद में प्रमुख इंफ्रास्ट्रकचर के विकास के लिए आयुध फैक्टरी, **रक्षा मंत्रालय** और **सीपीडब्ल्यूडी के** बीच **समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।**

iii. सीपीडब्ल्यूडी ने **2022 बैच के** नवनियुक्त जूनियर इंजीनियरों (सिविल, ईएंडएम) के लिए **26 सप्ताह का अनिवार्य फाउंडेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया, जो 22 मई, 2024 को पूरा हुआ।**

iv. 15 से 17 मई, 2024 तक जालंधर में **उद्यम संसाधन नियोजन (ईआरपी) कार्यान्वयन पर कार्यशाला आयोजित की गई।**

v. **ईआरपी कार्यान्वयन पर तीन दिवसीय कार्यशाला** 15 से 17 मई, 2024 तक जालंधर में और 01 से 03 मई, 2024 तक पुणे में आयोजित की गई।